Indian J. Soc. & Pol. 11 (01): 139-142 : 2024 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
(July-December 2023), 29 February 2024 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

'सांसद आदर्श ग्राम योजना' का एक दशक : ग्राम पंचायत जयापुर के विशेष सन्दर्भ में

आशीष सिंह[1]

[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, श्री महंथ रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भुड़कुड़ा, गाजीपुर,उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

देश की आजादी के बाद से ही सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं। अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों और किसानों को लाभान्वित करने का प्रयत्न किया जाता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज के सामाजिक,आर्थिक व राजनैतिक ढांचे में परिवर्तन भी परिलक्षित हुए हैं, किंतु ये परिवर्तन पर्याप्त नहीं कहे जा सकते आज भी भारतीय ग्राम विकास की दौड़ में काफी पिछड़े हुए हैं, आज भी भारत के गांवों में सड़क, विजली और शिक्षा आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास नहीं हो पाया है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं जिसमें एक प्रमुख कारण कार्य योजना निर्माण तथा इसके क्रियान्वयन में ग्रामीणों का समुचित भागीदारी का न होना है। 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के द्वारा इस कमी को काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया गया है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है, वे स्वयं अपनी आवश्यकताओं को सरकार के सम्मुख रखेंगे जिससे उचित योजना निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा।

KEYWORDS: *नियोजन, विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, नरेन्द्र मोदी, जयापुर*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारम्भ पर अपना विचार साझा किया गया आपके शब्दों में– हमारे लिए एक बड़ी समस्या रही है कि हमारा विकास, आपूर्ति उन्मुख रहा है। लखनऊ, गांधीनगर अथवा दिल्ली मे एक स्किम तैयार की गयी है इसे ही आरम्भ करने का प्रयास किया जा रहा है, हम आदर्श ग्राम के द्वारा इस मॉडल को आपूर्ति उन्मुख की वजाय मांग उन्मुख करना चाहते हैं, स्वयं ग्राम में ही इसकी इच्छा विकसित की जानी चाहिए, हमें केवल अपने विचार में परिवर्तन करना है, हमें लोगों के दिलों को जोड़ना है। सामान्यतः सांसद राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं लेकिन इसके बाद वे ग्राम में आएंगे। वहां कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी, यह परिवार की तरह होगा । गांव के लोगों के साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा। इसमें नयी ऊर्जा का संचार होगा और ग्रामीण एकजुटता में वृद्धि होगी' ।(https://www.pmindia.gov.in/hi/)

इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर,2014 को हुई थी, इसके पहले चरण (2014–2019) में 1509 तथा दूसरे चरण (2019–2024) में 1435 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जयापुर ग्राम पंचायत का चयन 7 नवम्बर 2014 को किया गया था जिसको अब तक एक दशक पूर्ण होने को है इस दौरान इस योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यो तथा उसके उपरांत ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक संरचना का विवरण इस शोध अध्ययन द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे निम्न विन्दुओं द्वारा उल्लेखित किया जा रहा है।

व्यवसाय

भारतीय गांवों की प्रमुख विशेषता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जिससे जयापुर गांव भी अछूता नहीं है ,इस गांव की मुख्य विशेषता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही है, सभी परिवार किसी न किसी रूप में कृषि कार्यो से जुड़े हुए हैं। जयापुर ग्राम पंचायत में कई जातियां संयुक्त रूप से निवास करती हैं, ये अपने परम्परागत तौर–तरीके तथा जातीय व्यवसाय में लगे हुए हैं जिससे यहां पर आज भी जजमानी प्रथा के अवशेष प्राप्त होते हैं यहां सेवा देने वाले परिवार जो जातीय व्यवसाय में में लगे होते है परजा (प्रजा) कहा जाता है। यहां की प्रमुख विशेषता है कि परिवार का एक सदस्य (मुखिया प्रमुख व्यक्ति) परंपरागत कार्यों में सक्रियता से लगा होता है तथा अन्य सदस्य सहयोगी की भूमिका में होते हैं। ये अन्य सदस्य देखने में तो कार्यशील प्रतीत होते हैं, किन्तु इनका उत्पादन में प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता। जिससे 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके लिए ग्रामीण सदैव नवाचार या किसी अन्य व्यवसायिक गतिविधियों हेतु तत्पर रहते है किन्तु अवसर के अभाव में वे परम्परागत कार्य से ही संतुष्ट हो जाते हैं और भरण–पोषण में व्यस्त रहते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना ने उनके इस मांग को समझा है तथा उनके लिए नए व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त किया है। यही प्रमुख कारण है कि लोगों ने इस योजना का जोरदार तरीके से स्वागत किया है।

शिक्षा एवं जागरुकता

जयापुर गांव में प्राइमरी (5वी) तक ही स्कूल की सुविधा उपलब्ध है इसके उपरांत शिक्षा हेतु बच्चो को गांव से बाहर दूर जाना पड़ता है। यदि आकड़ों के हवाले से देखें या धरातलीय स्तर पर स्कूलों में नामांकन के व्योरा का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि जयापुर ग्राम पंचायत अपने अगल–बगल के अन्य ग्राम पंचायतों की भाँति परिलक्षित होता है किन्तु जयापुर ग्राम पंचायत के विधार्थियों एवं अभिभावकों में एक अलग ही प्रकार का उत्साह और मनःस्थिति दिखाई देती है जो उन्हें कुछ मामलों में अन्य ग्रामपंचायतों से अलग करती है। जयापुर ग्राम पंचायत के लोग स्वयं को शासन कौर व्यवसाय से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जिसके कारण शिक्षा के प्रति

1: Corresponding Author

उनकी जागरुकता अलग तरह की दिखाई देती है। अन्य ग्रामपंचायत के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि यह उनके जीवनशैली का हिस्सा है। अधिकांश परिवारों में यह कार्य स्वतः ही हो जाता है। अभिभावक के जागरूकता का स्तर चाहे कुछ भी हो, सामान्यतः 5 साल की उम्र हो जाने के बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि गांव के सभी लोग ऐसा करते हैं अर्थात् यही इनकी जीवनशैली और दिनचर्चा है। जयापुर ग्राम पंचायत की भी सामान्य विशेषता यही है। किन्तु एक विशेषता जो स्कूलों का चयन करना है वह इन्हें थोड़ा अलग करती है जयापुर ग्राम पंचायत के लोग अपने बच्चो के स्कूल के चयन के अपनी आर्थिक स्थिति के अलावा इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि कौन से स्कूल का औरा बेहतर है।

स्वास्थ्य व्यवस्था

(1) आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता –

जयापुर ग्राम पंचायत का नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र जाखिनी में है जो 4 किमी. की दूरी पर अवस्थित है, अस्पताल का माहौल शान्तिपूर्ण और सच्चा है तथा यहां पर 24 घंटे सहयोगपूर्ण सेवा प्रदान की जाती है, किन्तु आधुनिक मशीनों आदि की उपलब्धता न के बराबर है जिसके कारण जयापुर ग्राम के लोग छोटी, मोटी समस्यायों जुकाम, आदि हल्का बुखार आदि के लिए किसी भी लोकल डाक्टर जिन्हें स्थानीय भाषा में झोलाछाप भी बोल दिया जाता है से दवाएं प्राप्त कर लेते हैं तथा गम्भीर बीमारी की स्थिति में वाराणसी (लगभग 30 किमी). जाना पड़ता है. हालांकि सड़कें और परिवहन संसाधन बेहतर हुए है किन्तु अभी भी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु भारत के अन्य ग्रामों की भांति जयापुर को भी संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ता है, अतः यहां पर आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग अभी भी बनी हुई है।

2) परम्परागत उपचार –

आधुनिकता के दौड़ में जहाँ विकास का पैमाना ही आधुनिक सेवाओं तक पहुंच माना जाता है भारत के गांव अभी भी अपने कुछ परम्परागत तरीकों और व्यवस्थाओं को संजोए हुए है। इनमें से एक प्रमुख उपचार व्यवस्था भी है जयापुर गांव के अनपढ़ बुजुर्ग व्यक्ति को भी ऐसे स्थानीय जड़ी बूटियों की जानकारी है जिनकी उपयोगिता है काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इनके प्रति विश्वास में कमी आई है किन्तु आज भी गांवों में हल्क–फुल्के बीमारियों का इलाज इन जड़ी–बूटियों से हो जाता है। सामान्य जुकाम होने पर तुलसी के पत्तो, अदरक आदि का काढ़ा बनाकर पीना एक आम बात है, गिलोय, हल्दी देशी घी आदि का उपयोग सामान्य उपचारों हेतु किया जाता है

आदर्श ग्राम स्थानीय विकास एवं सुशासन का संस्थान

भारत के गावों की यह प्रमुख समस्या रही है कि लोगों में सरकारी योजनाओं के प्रति जानकारी और जागरूकता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण. वे योजनाओं का समुचित लाभ नही ले पाते। सांसद आदर्श ग्राम् बन जाने से, लोगों की सरकारी योजना को बनाने में भागीदार बनाया गया, जिससे उन्हें अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जागरूकता का विकास हुआ। आदर्श ग्राम ने अपना विकास सुनिश्चित किया और स्वरोजगार की तरफ उन्मुख हुए हैं। स्थानीय विकास के प्रति लोगों में जागरुकता आ जाने से कई सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ लेने में सक्षम हुए हैं। सरकार के द्वारा लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया गया, महिलाओं को धागा बुनाई की मशीन उपलब्ध करायी गई जिसपर महिलाएं समूह बनाकर कार्य करती हैं जिसे सेवापुरी पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए महिलाएं अपने खाली समय का प्रयोग करती हैं जिससे उनके दिनचर्या में विशेष प्रभाव भी नही पड़ता और कुछ अतिरिक्त धन का उपार्जन भी हो जाता है।

ग्राम पंचायतों हेतु प्रेरणा

'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के तहत गोद लिए गए गांव अन्य गार्यों हेतु प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। जयापुर ग्राम पंचायत का सरकारी योजनाओं के प्रति जागरुकता, स्वयंसेवी समूहों का निर्माण आदि विषय अन्य ग्राम पंचायतों हेतु प्रेरणास्रोत बने हुए है । जयापुर के अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायत भी लाभ ले रहे हैं। महिलायें छोटे छोटे समूह बनाकर कुछ निश्चित राशि जमा करती हैं. 1 जिससे एक एक ही राशि जमा होती रहती है जिसे वे आवश्यकतानुसार उपयोग करती हैं। इसके अतिरिक्त समूह बनाकर लघु बैंकों से लोन भी प्राप्त करती है, जिसे अधिकतर नवाचार अथवा पुराने उद्यमों को विस्तार देने में उपयोग में लाया जाता है ।

परिवहन व्यवस्था

प्रधानमंत्री द्वारा गांव को गोद लेने के बाद सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य के अलावा बस स्टैण्ड भी बनाया गया है। एक प्राईवेट बस भी चलायी गयी थी किन्तु अब यह बंद हो चुकी है। चूंकि बस स्टैण्ड गांव के बाहर मुख्य सड़क पर बनी हुई है इसलिए यह लोगों के चौपाल की जगह बन गयी है। यहां हर समय दो चार लोग बैठकर गपशप करते मिल जाएंगे। यहीं पर बैठे कन्हेलाल जी ने बताया कि बस सर्विस की व्यवस्था जलान वाले लोगों के द्वारा किया गया था। उन्होंने बस की व्यवस्था की और उसे गांव वालों को सौंप दिया। लेकिन सवारियों की संख्या कम होने के कारण उसका खर्च निकल पाना भी सम्भव नहीं हो सका। ड्राईबर को तनप्ताह भी नहीं मिल पा रहा था इसलिए उसे बन्द करना पड़ा। सवारी न मिलने का कारण उन्होंने बताया कि यहां से टैम्पू चलते हैं जो हर समय (सवारी मिल जाने पर। चलते रहते हैं, जबकि बस का एक समय निर्धारित था जिसके साथ सामंजस्य बैठा पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, और उन्होने टैम्पों को ही पसन्द किया। हालांकि एक सीटी बस का संचालन अब भी हो रहा है जो दिन में दो चक्कर लगाती है। बस स्टैण्ड जो कि पंचायत भवन परिसर में ही रोड़ के किनारे अवस्थित है।

सौर उर्जा संयंत्र

गांव में जगह– जगह पर सौर उर्जा से चलने वाले बल्ब लगाए गये हैं, जिनमें से कुछ खराब हो चुके हैं, कुछ बैटरी ही गायब हैं। गोद लेने के बाद गांव में यूनियन बैंक आफ इडिया द्वारा

एक शाखा की स्थापना भी की गयी है, इस बैंक द्वारा भी कुछ सोलर प्लेट, बैट्री और खंभे लगवाये गए है। गांव में एक सोलर प्लान्ट भी लगवाया गया है जिससे विजली का उत्पादन होता है, और वह लाईट (बल्ब) जलाने के काम में ली जाती है, इसके सप्लाई का समय शाम 6 बजे से रात 10 वजे तक तथा सुबह में 4 बजे से 6 बजे तक रहता है, सोलर प्लांट की तरफ से जगह–जगह पर खंभे की व्यवस्था भी की गयी है, जहा बैट्री भी लगाया गया है। लेकिन इसमें से कुछ बैटरी गायब (खराब अथवा चोरी) भी हो चुकी है।गांव में चल रहे इस संयंत्र को 'वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लि. नोएडा' द्वारा रुपया 3 करोड़ की लागत सें लगाया गया था। जिसकी क्षमता 25 किलोवाट है। इस सयंत्रो से गांव के प्रत्येक घर को 2 एल.ई.डी बल्ब एवम 1 मोबाईल चार्जिग प्वाइंट मुफ्त दिया जा रहा है।

विजली व्यवस्था

बिजली व्यवस्था का गांव के गोंद लेने के पूर्व की अवस्था का विवेचन करें तो हम पाते हैं कि पूर्व में यहां विजली व्यवस्था की स्थिति खस्ता हाल थी। 24 घंटे में 8 तक घंटे एक विजली मिलना भी मुश्किल हो जाता था जिसकी कारण मूलभूत कार्य जैसे खेतो की सिचाई कुटीर उद्योग (आटा चक्की आदि) भी बड़ी मश्किल से चल पा रहे थे। ठंड के मौसम में यदि बिजली, रात में आती थी– तो ठिठुरते ठंड में भी किसानों को रात में जाकर खेतों की सिचाई करनी पड़ती थी, जो काफी कष्टप्रद स्थिति थी लेकिन गांव को गोद लेते ही बिजली व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ। पुराने जर्जर तार और बिजली के खंभे बदल दिये गये हैं। गांव की प्राइमरी पाठशाला में बिजली पहुंचायी गयी और पंखे भी लगाए गए है।

बैंक की सुविधाएं

गांव को गोद लिए जाने के पूर्व गांव में किसी भी बैंक की कोई शाखा नही थी गांव वालों को बैंक की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए जखिनी (पोखरा मोड़) जाना पड़ता था। दूरी अधिक होने के कारण बैंकिंग सुविधाओ का संपूर्ण लाभ गांव के लोग नही ले पाते थे किंतु गांव को गोद ले लिए जाने के बाद 'यूनियन बैंक ऑफ इंडिया' के द्वारा गांव में एक शाखा की स्थापना नवंबर 2014 में की गई। इस मौके पर गांव के ऐसे 30 लोगो को जो किसी न किसी ट्रेड में तकनीकी शिक्षा ले चुके थे स्वरोजगार के लिए 21 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। इसके साथ ही साथ उद्घाटन के मौके पर ही बैंक ने 25 महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने का निश्चय किया। यह शाखा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा के द्वारा ही अपने विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस शाखा की सबसे प्रमुख और खास विशेषता यह है कि बैंक द्वारा लगाए गए सौर संयंत्र से यह 'कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' के अंतर्गत गांव के आंगनवाड़ी केंद्र 5 पखे, 5 सोलर स्ट्रीट लाइट ओर बैंक के पास ही एक हैंडपंप भी लगवाया गया।(अमर उजाला 18.09. 2023)

सामाजिक विकास

इस योजना में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक सेवाओं तक लोगों के पहुंच में सुधार को सुनिश्चित किया जाता है। स्वरोजगार के प्रति जागरुकता इस योजना के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। खासकर गांव की महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति सकारात्मक जागरुकता का संचार हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार योजना से पूर्व और बाद की स्थितियों में काफी परिवर्तन हुआ है। योजना पूर्व गांव की महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति कोई उत्सुकता नहीं थी किन्तु अब अधिकतर महिलाएं स्वरोजगार में लगी हुई हैं और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझने लगी हैं।

उपसंहार

'सांसद आदर्श ग्राम योजना' वास्तव में गांव को आदर्श गांव बनाने हेतु संकल्पित एक योजना है। एक ऐसा आदर्श जिसे स्थापित करने में अत्यधिक जागरुकता, सरकारी सहायता और सतत विकास की आवश्यकता है। जिस, आदर्श की कल्पना सरकार और स्थानीय लोगों द्वारा की गयी है, उसके लिए स्थानीय स्वशासन की मजबूती, प्रत्येक स्तर पर सरकार द्वारा अपेक्षित सहयोग और जागरुकता का उच्च स्तर सतत रूप से बने रहने की आवश्यकता है। गांव को गोद ले लेने और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करने से स्थानीय लोगों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। जिसे बनाए रखते हुए सतत विकास के क्रम में आगे बढ़ते रहने से ही उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में निरन्तर बढ़ा जा सकता है। गांव के वैयक्तिक अध्ययन के दौरान यह काफी सकारात्मक पहलू देखने को मिला कि लोगों में काफी उत्साह है स्थानीय लोगों से बात करने के दौरान ऐसे लोगों से भी चर्चा हुई जो कराए गए कार्यो की कमियां गिनाते मिले। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने उम्मीद के मुताविक काम न होते की बात की किन्तु ऐसे एक भी एक व्यक्ति को ढूंढ पाना सम्भव न हो सका जो इस योजना से असन्तुष्ट दिखाई पड़ें

ग्राम सभा के लगभग सभी व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया कि उनके इस योजना के आ जाने के बाद उनके जागरुकता के स्तर और सरकार के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है। लोगों का यहां तक कहना है कि सही मायने में लोकतन्त्र की सार्थकता इसी में हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को शासन के साथ जुड़ा हुआ महसूस करे और विकास कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, यह योजना विकास के स्तर पर चाहे जैसे मूल्यांकित किया जाए किन्तु ग्रामीणों के सरकार ने प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है अतुलनीय है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह योजना शिथिल पड़ती दिख रही है। अब सांसद और अधिकारीगण इस योजना के प्रति उदासीन हो चले हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें एक प्रमुख कारण भौतिक विकास का उस स्तर तक परिलक्षित न होना जैसा उम्मीद किया जा रहा था, किन्तु इसके सामाजिक पहलू को देखें तो गांव के भोले–भाले लोगों के लिए यह योजना काफी लाभप्रद है। उनके जागरुकता के स्तर में सुधार लाने के लिए इन योजनाओं का काफी लाभ प्राप्त होता है सामान्यता गांव के सीधे साधे लोग अपने मताधिकार की शक्ति से पहचानने में अक्षम प्रतीत होते हैं। गांव में एक सामान्य मुहावरा प्रचलित है। चाहे कोई की सरकार आये हमारे

खेतों में हल तो हमें ही चलाना है अर्थात् उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति का आंकलन सरकार में बैठे लोग नहीं लगा सकते। उनकी अपनी अलग जीवनशैली होती है। किन्तु इस योजना के माध्यम से लोगों को अनुभूत हुआ है, कि सरकार में बैठे लोग हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारी फिक्र करते हैं और शासन की सहायता स्वयं के एवम सामुदायिक विकास में ली जा सकती है। कई तरह सरकारी और गैर–सरकारी उद्यमों द्वारा मिल रहे लाभों की जानकारी और जागरूकता में विकास हुआ है।

REFERENCES

https://www.pmindia.gov.in/hi/ accessed on 18.10.2023

अमर उजाला, 18.09.2023